P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

डिजिटल क्रांति और ग्रामीण विकास

Digital Revolution and Rural Development

Paper Submission: 03/06/2021, Date of Acceptance: 14/06/2021, Date of Publication: 24/06/2021

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय टी.सी.एल.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जांजगीर, जिला–जांजगीर
चाम्पा, छ.ग., भारत

सारांश

भारत में जब संचार क्रांति की शुरूआत हुई थी, तो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह विकास में ही योगदान नहीं देगा, बल्कि उनकी जीविका का साधन बन जायेगा। संचार सुविधाओं की ही देन है कि आज बड़े ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे–जैसे संचार सुविधाओं का विस्तार होगा, वैसे–वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें।

संचार क्रांति कृषि विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संचार क्रांति से कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी कृषकों को पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर और समय से मिल रही है।

डिजिटल इंडिया ने देश में डिजिटल सोच, डिजिटल नवोन्मेष, डिजिटल जागरूकता और डिजिटल महत्वाकांक्षा का माहौल बना दिया है। निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियॉ भी डिजिटल इंडिया से जुड़कर गौरव का अनुभव कर रही है।

डिजिटल ग्रामीण शिक्षा न केवल उद्यमिता का सूत्रपात करती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्तर को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण मानकों में सुधार लाती है। गॉवों में गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और पुरूषों में भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

गॉवों में बसने वाला भारत अब ई–क्रांति का अग्रदूत बनने की राह पर है।

When the communication revolution was started in India, people did not even dream that it would not only contribute to the development but would become a means of their livelihood. It is because of the communication facilities that today not only adults but children are also using the internet. There is no doubt that as the communication facilities expand, so will the employment opportunities.

Communication revolution is also playing an important role in the direction of agricultural development. Due to the communication revolution, farmers are getting technical information related to agriculture many times better and in time than before.

Digital India has created an environment of digital thinking, digital innovation, digital awareness and digital ambition in the country. Private sector and multinational companies are also feeling proud to be associated with Digital India.

Digital rural education not only initiates entrepreneurship but also influences the socio-economic status in the rural area. Improves rural standards. It also plays an important role in eradicating poverty in villages, eradicating discrimination between women and men.

India settled in villages is now on its way to become the harbinger of e-revolution.

मुख्य शब्द : संचार माध्यम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य आवश्यकता, ग्रामीण विकास, ग्रामीण भारत के समक्ष चुनौतियॉं, डिजिटल क्रांति का प्रभाव

Media, Objectives of Digital India Program, Need, Rural Development, Challenges before Rural India, Impact of Digital Revolution

प्रस्तावना

2015 में प्रारंभ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने और डिजिटल अंतराल को पाटकर भात को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल स्वरूप में सशक्त समाज में परिवर्तित करने की बात सोची गयी है।

इस कार्यक्रम में अपनी मजबूत समाज में परिवर्तन करने की बात सोची गयी है। इस कार्यक्रम ने अपनी मजबूत डिजिटल अवसंरचना तक सब लोगों की पहुंच सुनिश्चित करके उनका डिजिटल समावेशन सुनिश्चित किया है शेष दुनिया के साथ उनके संपर्क को आसान बना दिया है। इसने ऐसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक भागीदारी और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया है। जो आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली और चिरस्थायी है।

देश के समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है। सन् 2025 तक एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। पिछले 6 वर्षो के दौरान देश में डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कागज विहीन, उपस्थिति विहीन और नकदी विहीन शासन प्रदान करने के लिए डिजिटल उपकरणों और तकनीकों के उपयोग पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करके किया गया।

आधार ने डिजिटल पहचान की नींव डाली जो विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाईन और सत्यापन योग्य है। आधार समन्वित, डिजिलॉकर ने कागज विहीन प्रशासन को संभव बना दिया है अब नागरिकों को सार्वजनिक दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होने लगे है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी सहमति पर आधारित डेटा साझेदारी की सुविधा उपलब्ध है। आधार समन्वित ई–साईन ने डिजिटल लेन–देन के लिए सत्यापन को आसान बना दिया है। इस तरह व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली से बैंकिग सेवाएं और डिजिटल भुगतान आसान हो गए है।

जनधन, आधार और मोबाईल अर्थात् ''जैम'' त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाने वाली इन तीन योजनाओं में से प्रत्येक योजना नागरिक केन्द्रित सेवाओं में सामूहिक रूप से और अलग–अलग भी उत्कृष्ट मददगार नजर आती है। जन–धन योजना ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान किया है। मोबाईल फोन ने दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रो में सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान किया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की नागरिक केन्द्रित कुछ महत्वूर्ण योजनाएं निम्नलिखित है–

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण – सरकार की ओर से दिए जाने वाले लाभों को सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करता है।
2. डिजिलॉकर – नागरिकों को उनके सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी जगह उपलब्ध कराकर कागज विहीन अभिशासन उपलबध कराता है।
3. उमंग – अनेक सरकारी एप्लिकेशन्स और डेटाबेसेज के साथ बैंक एण्ड समन्वय के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाला संपूर्ण मोबाईल एप।
4. ई अस्पताल – हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सिस्टम के 20 से अधिक मॉडल के माध्यम से अस्पतालों में रोगी पंजीकरण, आईपीडी, फार्मेसी, ब्लड बैंक जैसी गतिविधियों के स्वचालन को आसान बनाता है।
5. ई–नाम – 16 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 585 कृषि मंडियो का समन्वय।
6. स्वयं – मैसिव ऑनलाईन ओपन कोर्स प्लेटफार्म के माध्यम से 2000 से अधिक कार्यक्रम श्रेणियाँ। पाठ्यक्रम पूरा होने पर विद्यार्थियों को क्रेडिट उपलब्ध कराता है जो विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
7. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल– एकल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराता है।
8. पी.एम.जी. दिशा – प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ किया गया।
9. इंडिया बी.पी.ओ. योजना – 108 छोटे शहरों में बी.पी.ओ. रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए 276 इकाईयां स्वीकृत की गई।
10. जी.ई.एम. – यह आम इस्तेमाल की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई–कामर्स प्लेटफार्म है।
11. डिजिटल भुगतान – कई नए डिजिटल भुगतान टूल जैसे भीम एप, भीम आधार, भारत क्यूआर कोड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन्स प्रारंभ किये गये।
12. जीवन प्रमाण – इससे पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है।
13. ई–कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों में ऑटोमेशन को प्रोत्साहन देता है।
14. माईगव (मेरी सरकार)– साझा डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर देश में सहभागिता पूर्ण अभिशासन में मदद करता है। जिसमें नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सकते है।

अध्ययन विधि

द्वितीयक समंको पर आधारित

साहित्याावलोकन

डॉ. रूपसी तिवारी, बी.पी.सिंह, डॉ. राहुल तिवारी[1] के अनुसार – परम्परागत संचार माध्यमों ने देश की विकास प्रक्रिया में बहुत योगदान दिया है। ये संचार माध्यम नई पीढ़ी में हमारी परम्परा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करते रहे है। प्रो. पी. पुरूषोत्तम[2] के अनुसार – गरीबों को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाना गरीबी उन्मूलन की किसी भी रणनीति का महत्वपूर्ण तत्व माना जाने लगा है। अरविन्द कुमार सिंह[3] के अनुसार – ग्रामीण विकास में मीडिया बहुत कारगर

हथियार बन सकता है। डॉ. आलोक शर्मा[4] के अनुसार – आधुनिक समाज में सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नवीन महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका ग्रहण कर ली है। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। सुभाष सेतिया[5] के अनुसार – सूचना तकनीक 21वीं सदी का सबसे प्रभावकारी तंत्र है, जिसमें दुनिया भर में बदलाव के नए युग का सूत्रपात किया है। डॉ. कल्पना द्विवेदी[6] के अनुसार – भारत जैसे कृषि प्रधान देशो में डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपयोगिता कुछ ज्यादा ही है इससे ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि सर्वाधिक लाभान्वित हो सकती है। कृषि संबंधित अद्यतन एवं उपयोगी जानकारी जुटाने का यह अत्यंत उपयोगी माध्यम है। ललन कुमार महतो[7] के अनुसार – ग्रामीण भारत के बदलते सामाजिक परिवेश में डिजिटल इंडिया एक क्रांति के रूप में अग्रसित होने की संभावना है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गॉवों के लोगों में संचार क्रांति, वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्रों में दूरगामी परिवर्तन आने की संभावना है। डॉ. नीरज कुमार गौतम[8] के अनुसार – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाईल के माध्यम से गांव के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंटरनेट और तकनीक का विस्तार प्रस्तावित सभी दिशाओं में तेजी से हुआ है। आधुनिक तकनीक और डाटा प्रबंधन ने सरकार और नागरिकों के बीच के अंतर को पाटा है। इसका सीधा असर नागरिक सहभागिता और जनजागरूकता पर पड़ता है। जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। ओंकार राय[9] के अनुसार – सहभागिता पूर्ण, समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार के निर्माण की पृष्ठभूमि में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नागरिकों को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाकर सबसे बड़े लोकतंत्र को सुदृढ़ लोकतंत्र में बदलने की दिशा में नयी पारी के आगाज का संकेतक है। दीपक शर्मा, कामिनी मलिक जयवर्द्धन[10] के अनुसार – भारत में डिजिटल अंत्योदय की शुरूआत हो चुकी है। शिक्षा, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य और रहन सहन का बेहतर स्तर, सामाजिक सुरक्षा आदि सामाजिक आर्थिक अधिकारों की गारंटी की मांग जोर पकड़ रही है। भारत ने इस दिशा में तकनीक की मदद से उदाहरण पेश किया है। जिसके अंतर्गत सामाजिक अर्थिक अधिकारों का समर्थन किया गया है। समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

नीरज सिंह और एस मोहित राव 11 के अनुसार–डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की परिकल्पना निहित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक भाग में तीव्रगति से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अशोक सिंह 12 के अनुसार– कोविड–19 महामारी के बाद डिजिटल लेनदेन कईगुना बढ़ गया है। यह परिवर्तन गॉवो में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। गजेन्द्र सिंह मधुसूदन 13 के अनुसार–भारत की डिजिटल यात्रा ने सशक्तिकरण, समावेशन एव डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं में महसूस किया जा रहा है। डॉ. रवीन्द्रनाथ लेंका, अवनीश त्रिपाठी 14 के अनुसार–भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। जिसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल कार्यक्रम और आभासी (वर्चुअल) कक्षाओं की भारत के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमि का होगी। डॉ. वीरेन्द्र कुमार 15 के अनुसार–सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जिसके अंतर्गत ई–प्रशासन को प्रोत्साहन देने के साथ अर्थव्यवस्था मे सुधार का लक्ष्य है।

ग्रामीण भारत के समक्ष चुनौतियॉ

1. स्तरीय शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना।
2. शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना।
3. नारी सशक्तिकरण की दिशा में सूचना और सहभागिता को सहज करना।
4. जनोपयोगी योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन के लिए मंच उपलब्ध कराना।
5. रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध कराना।
6. जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना।
7. प्रशासन और नागरिक सेवाओं को आसान् और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना।
8. खेती और किसान को मुख्यधारा से जोड़ना।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता

भारत उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यहॉ व्यापक सहभागिता वाला लोकतंत्र विकसित हो, अर्थात् एक ऐसी व्यवस्था जहॉ आर्थिक और सामाजिक मतभेदों से परे सभी नागरिकों की पहुॅच सार्वजनिक सूचनाओं तक हो सरकारी नीतियों पर बहस में ये हिस्सा ले सके तथा राष्ट्र के नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी हो। शासन अब एक तरफ प्रक्रिया न होकर अधिक समावेशी, विचार–विमर्श और सह–सृजन की प्रक्रिया बन गया हैं। युवाओं की अधिक आबादी वाले भारत जैसे प्रगतिवादी देश में ऐसे राष्ट्र राज्य की परिकल्पना करना तर्कसंगत है जहॉ सामाजिक आर्थिक सूचकांक को बेहतर करने के लिए परिवर्तन जरूरी है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) के तेजी से हो रहे विकास ने सरकार को यह सोचने पर विवश कर दिया कि क्यों न आई टी को ही विकास का प्रमुख माध्यम बनाया जाए। इस क्रम में शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को डिजिटली तौर पर जोड़ा जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाकर शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं की वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन करना।

2. नागरिकों को डिजिटली तौर पर सहज बनाने और पारदर्शी स्मार्ट गवर्नेस से जुड़ी जानकारियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।
3. भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित करना।
4. ग्रामीण विकास में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिका का अध्ययन।

डिजिटल क्रांति का प्रभाव

कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि उत्पादन पर ही गॉवों की खुशहाली निर्भर करती है। केन्द्र सरकार की सहायता से विभिन्न राज्य सरकारें ई–कृषि की ओर अग्रसर है। कृषि के साथ–साथ पंचायतों के कामकाज को कारगर और सुचारू बनाने के लिए ई–प्रशासन योजना प्रभावकारी है। इसके अंतर्गत भूमि के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, राशनकार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य काम इसके अंतर्गत संचालित है। गॉवो में संचार सुविधाओं के विकास के साथ ही सरकारी सुविधाओं का भी विकास हुआ है। जिन गॉवो में इंटरनेट की सुविधा है वहॉ किसी भी तरह की समस्या हो, तुरन्त इन्टरनेट के माध्यम से इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंचा दी जाती है।

ग्रामीण विकास में सूचना संचार तकनीक के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब मिट्टी के घरो में भी मोबाईल की घंटियॉं बजती है।

संचार क्रांति ने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। इंटरनेट संचार क्रांति का केन्द्र बिन्दु है। सूचनाओं का आदान–प्रदान और उन्हे पलक झपकते ही एक कोने से दुसरे कोने में पहुंचा देना अब बेहद आसान हो चुका है। हाल ही में तमिलनाडु में सरकार ने बाढ़पीड़ित 30.42 लाख परिवारों में से जिन 14 लाख पीड़ित परिवारों के ऑकड़े कम्प्यूटराइज्ड थे, उनके बैंक खातों में राहत राशि के 7 करोड रूपये एक दिन में ही पहुंचा दिए। संचार क्रांति का यह एक बेहतरीन उदाहरण है।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री का स्वप्न देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। एक उद्देश्य सबको सशक्त बनाने का और उन बेजुबानो की आवाज देने का है जिसकी बात की पहुंच सीमित रही है। गॉव के उस युवा को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की है, जो अपने सामान को पड़ोस वाले शहर तक ले जाने में भी असमर्थ था।

डिजिटल इंडिया सूचना क्रांति के दूसरे दौर का सूत्रपात कर सकती है। डिजिटल इंडिया को भारत की राजनैतिक – सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की ओर ले जाने के महत्वकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

विकास की सोच एवं दृष्टि तथा जनकल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में जनसंचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस समय गॉवो में साक्षरता दर निम्न थी, रेडियो तथा आकाशवाणी ने कृषि तथा ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया। वर्तमान में रेडियो, टी.व्ही. और प्रिन्ट मीडिया के साथ–साथ कम्प्यूटर से भी गॉवों के उत्थान को प्रोत्साहन देने वाली सूचनाओं का प्रसारण प्रकाशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तरह इंटरनेट भी अब नए संचार माध्यम के रूप में उभर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रो में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की रणनीति बनाते समय स्थानीय भाषा, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति व आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे तत्वों पर भी विचार किया जाए।

संचार क्रांति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए है। समय के साथ संचार प्रणाली सुदृढ़ हो रही है। संचार क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम प्रदान किए है।

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी की गूंज सशक्त समाज के गलियारों से आगे बढ़ गई है। सरकार प्रौद्योगिकी के बदलते परिदृश्य को अपना रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से जनता को समन्वित नागरिक केन्द्रित सेवाओं का लाभ मिले, समाज का कल्याण हो, देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

डिजिटल इंडिया एवं ग्रामीण भारत

1. लोक पत्रकारिता के नए आयाम के लिए – लोगों तक बेहतर सूचना प्रसारित की जा सकती है। स्थानीय लोगों को भी अपनी बातो को कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
2. शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग – तकनीकी के माध्यम से शिक्षक ऑनलाईन अपने विचारों और संसाधनो को साझा कर रहे है जो विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य सामग्री सिद्ध हो रही है।
3. स्वस्थ ग्रामीण भारत – ग्रामीण महिलाओं का गिरता स्वास्थ्य, कुपोषण, सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर, वर्तमान परिदृश्य में भारत की अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इससे निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन काफी हद तक सहायक हो सकता है।
4. स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का सहयोगी – ये परियोजनाएं डिजिटल इंडिया के साथ बेहतर परिणाम दे सकती है।
5. लोगों की समस्याओं का समाधान और जागरूकता के प्रसार के लिए – डिजिटल इंडिया का उपयोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े दूरदराज के गॉवों तक बिना रोक–टोक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।
6. महिला सशक्तिकरण के लिए – इसे आसानी से उन मुद्दो पर केन्द्रित किया जा सकता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले।

7. रोजगार के अवसर – डिजिटल इंडिया का सामाजिक पक्ष के साथ–साथ व्यवसायिक पक्ष भी है। गॉव के हर युवा को रोजगार मिले, इस योजना का लक्ष्य है।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ

डिजिटल इंडिया के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती मानव संसाधन की कमी है। देश में जितना मानव श्रम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियोजित है, उसे कई गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी किसी चुनौती से कम नहीं है। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की भी समस्या है।

निष्कर्ष

निसंदेह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ रहे है। गरीबी का स्तर कम हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सामाजिक बुराईयॉ कम हुई है। आज का ग्रामीण जागरूक हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ग्रामीण देश–विदेश से आ रहे परिवर्तन से परिचित हो रहा है। जिससे वे अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है।

ग्रामीण भारत के बदलते सामाजिक परिवेश में डिजिटल इंडिया एक क्रांति के रूप में अग्रसित होने की संभावना है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गॉवों के लोगों में संचार क्रांति, वित्तीय समावेशन आदि क्षेत्रो में दूरगामी परिवर्तन आने की भी संभावना है। यदि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो और पात्र अनुसार लाभ बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार या मनमानी के प्राप्त हो, तो तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निश्चित तौर पर वर्तमान समय की जरूरतों और दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशाल स्तर पर तैयार किया गया संतुलित कार्यक्रम है। जो दीर्घावधि में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उन्मुख होगा।

डिजिटल इंडिया ने डिजिटल प्लेटफार्म की शक्ति का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ प्रौद्योगिकी को अपनाकर चिरस्थायी और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर हो सकती है।

अंत टिप्पणी

1. *डॉ. रूपसी तिवारी, बी.पी. सिंह, डॉ. राहुल तिवारी – परम्परागत संचार माध्यम ग्रामीण विकास में भूमिका और प्रासंगिकता, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2003, पृ.क्र. 20*
2. *प्रो.पी. पुरूषोत्तम – ग्रामीण रोजगार में सूचना टेक्नोलॉजी की भूमिका, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2003, पृ. क्र. 55*
3. *अरविन्द कुमार सिंह – ग्रामीण विकास और मीडिया, कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2006, पृ.क्र. 37*
4. *डॉ. आलोक शर्मा – गॉवों के सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2011, पृ.क्र. 21*
5. *सुभाष सेतिया – गॉवों में सूचना टेक्नालॉजी का बढ़ता प्रभाव, कुरूक्षेत्र, जनवरी 2012, पृ.क्र. 21*
6. *डॉ. कल्पना द्विवेदी – डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण विकास, कुरूक्षेत्र, जुलाई 2014, पृ.क्र. 17*
7. *ललन कुमार महतो – डिजिटल क्रांति से बदलता ग्रामीण समाज, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2015, पृ.क्र. 41*
8. *डॉ. नीरज कुमार गौतम – मोबाईल क्रांति ने दी ग्रामीण विकास को नई दिशा, कुरूक्षेत्र, फरवरी 2016, पृ.क्र. 14*
9. *ओंकार राय – सशक्त डिजिटल समाज बनता भारत, योजना, मई 2017, पृ.क्र. 27*
10. *दीपक शर्मा, कामिनी मलिक, जय वर्द्धन – डिजिटल माध्यमों से गरीबों को उत्थान का लक्ष्य योजना, जुलाई 2019, पृ.क्र. 51*
11. *नीरज सिंह और एस. मोहित राव–डिजिटल इंडिया– नए भारत की आकांक्षा, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2020, पृ. क्र. 5*
12. *अशोक सिंह –साकार होती डिजिटल भारत की परिकल्पना, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2020, पृ.क्र. 16*
13. *गजेन्द्रसिह मधुसूदन–पारंपरिक अर्थव्यवथा से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2020, पृ.क्र. 22*
14. *डॉ. रवीन्द्रनाथ लेंका, अवनीश त्रिपाठी–ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा और वर्चुअल लर्निंग, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2020, पृ.क्र. 34*
15. *डॉ. वीरेन्द्र कुमार–किसानों के जीवन का अहम हिस्सा बनती डिजिटल टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2020, पृ.क्र. 38*

संदर्भ ग्रंथ सूची

कुरूक्षेत्र, दिसम्बर, 2020

1. *अक्टूबर 2001 –*
   i. *सूचना प्रौद्योगिकी बदलेगी गॉवों की तकदीर – अनंत मित्तल, पृ.क्र. 19*
   ii. *गॉवों को आधुनिक तकनीक चाहिए, पर परम्परा से जुड़ा रहना भी जरूरी है – भारत डोगरा, पृ.क्र. 65*
2. *अक्टूबर 2003 – ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों का योगदान – एक परिदृश्य – कृष्ण कल्कि, पृ.क्र. 4*
3. *नवम्बर 2004 – संचार क्रांति के युग में परम्परागत संचार माध्यमों की भूमिका – इंदल सिंह, भदौरिया, पृ.क्र. 24*
4. *सितम्बर 2005 –*
   i. *ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान – ओ.पी. शर्मा, पृ.क्र. 31*
   ii. *राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का ग्रामीण विकास में योगदान – गणेश कुमार पाठक, पृ.क्र. 34*
5. *दिसम्बर 2006 –ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की उपयोगिता – बलकार सिंह पूनिया, पृ.क्र. 45*
6. *अगस्त 2009 – गॉवों में संचार क्रांति ने खोले रोजगार के के नए द्वार– चंद्रभान चंदन, पृ.क्र. 38*

7. *अगस्त 2010 – गॉवों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बढ़ता दायरा – डॉ. निरंजन कुमार सिंह, पृ.क्र. 16*
8. *अक्टूबर 2011 – गॉवो में उत्थान में मीडिया की नई पहल – सुभाष सेतिया, पृ.क्र. 27*
9. *अक्टूबर 2012 – गॉवों में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार – बलवंत सिंह मौर्य, पृ.क्र. 10*
10. *मार्च 2014 – ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की वर्तमान स्थिति – सौरभ कुमार, पृ.क्र. 3*
11. *जुलाई 2014 –*
i. *ग्रामीण क्षेत्रो में जारी है प्रौद्योगिकी का नव प्रवर्तन – प्रोफसर हेमंत जोशी, पृ.क्र. 3*
ii. *अत्याधुनिक तकनीकों का ग्रामीण विकास में योगदान – जगपाल सिंह मलिक, पृ.क्र. 8*
12. *दिसम्बर 2014 – डिजिटल इंडिया – ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर, बालेन्दु शर्मा दाधीच, पृ.क्र. 29*
13. *दिसम्बर 2015 – स्मार्ट गॉव से सशक्त भारत – उमाशंकर मिश्र एवं डॉ. रश्मि बोहरा, पृ.क्र. 35*
14. *फरवरी 2016 –*
i. *इलेक्ट्रानिक मीडिया और गॉवों का बदलता चेहरा – प्रभांशु ओझा, पृ.क्र. 10*
ii. *सूचना तकनीक से गॉवो में उद्यमिता का नया माहौल – बालेन्दु शर्मा दाधीच, पृ.क्र. 25*
iii. *किसानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की चुनौतियाँ– गिरेन्द्रनाथ झा, पृ.क्र. 39*
15. *नवम्बर 2019 – डिजिटल साक्षरता की दिशा में मजबूत कदम – बालेन्दु शर्मा दाधीच, पृ.क्र. 34*
16. *दिसम्बर 2020 –*
i. *डिजिटलीकरण–स्मार्ट गॉव की अवधारणा का प्रमुख घटक–पार्थ प्रतिमसाहू, पृ.क्र. 43*
ii. *डिजिटल साक्षरता से सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं–डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी, पृ.क्र. 47*
iii. *डिजिटलीकरण से शुरू हुआ जीवन का नया सफर–सन्नी कुमार, पृ.क्र. 51*

योजना

1. *अप्रैल 1998 – ग्रामीण विकास का लेखा–जोखा – सुन्दरलाल कुकरेजा, पृ.क्र. 3*
2. *जनवरी 2020 – सूचना प्रौद्योगिकी और इसके प्रयोग – शेफाली एस.दास, पृ.क्र. 12*
3. *जनवरी 2002 –*
i. *कैसी हो ग्रामीण विकास की दिशा – भारत डोंगरा, पृ.क्र. 38*
ii. *ग्रामीण संचार में भागीदारी की ओर – जे. भाग्यलक्ष्मी, पृ.क्र. 65*
4. *नवम्बर 2010 – दूरसंचार सेवाएं – कल आज और कल –सतीश चन्द्र सक्सेना, पृ.क्र. 37*
5. *सितम्बर 2012 – संचार क्रांति एवं सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य, दुर्गादत्त ओझा, पृ.क्र. 31*
6. *जुलाई 2013 – ग्रामीण विकास की धुरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया – कुलदीप शर्मा, डी.डी. बंसवाल, पृ.क्र. 52*
7. *सितम्बर 2015 – गॉव होगें स्मार्टनेस की असली कुंजी – संजय श्रीवास्तव, पृ.क्र. 33*
8. *जनवरी 2016 – डिजिटल इंडिया से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर – संदीप कुमार पाण्डेय, पृ.क्र. 45*
9. *जून 2020 –डिजिटल इंडिया–डॉ. शीतल कपूर, पृ.क्र. 21*
10. *जुलाई 2020 – कोविड–19 से डिजिटल सुरक्षा–सौरभ गौड़, ऋचा रश्मि, पृ.क्र. 51*